भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 734 का उत्तर

कोलकाता मेट्रो स्टेशनों में प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे/स्लाइडिंग दरवाजे लगाना

734. श्रीमती माला राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलकाता मेट्रो स्टेशनों में प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे/स्लाइडिंग दरवाजे लगाने से संबंधित कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आत्महत्या करने के प्रयासों को रोकने के लिए कोलकाता मेट्रो के सभी प्लेटफॉर्मों पर स्लाइडिंग दरवाजा लगाने का कार्य पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भूमिगत स्टेशनों में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पूरी ऊंचाई) और ऊंचाई/समतल पर बने मेट्रो स्टेशनों में प्लेटफॉर्म स्क्रीन गेट (आधी ऊंचाई) की संकल्पना परियोजना नियोजन चरण में ही तैयार की जाती है। इस व्यवस्था की आवश्यकता निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करती है-

(i) स्टेशनों में अधिकतम यात्री भार के समायोजन के लिए चौड़े प्लेटफार्मों के लिए पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर/प्लेटफॉर्म स्क्रीन गेट अधिकतम अधिभोग के लिए प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्र को अनुकूलित करता है।

(ii) वातानुकूलित भूमिगत स्टेशन के मामले में वातानुकूलन क्षति को कम करना। पूर्ण ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर ट्रेनवे में वातानुकूलन क्षति को समाप्त कर देता है।

प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर/प्लेटफॉर्म स्क्रीन गेट दरवाजे एकल प्रणाली नहीं हैं और यह सिगनल प्रणाली और रेलगाड़ी नियंत्रण प्रणाली के साथ एकीकृत हैं। वर्तमान में, कोलकाता मेट्रो नेटवर्क में, ग्रीन लाइन (पूर्व - पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर) के सभी 12 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर/प्लेटफॉर्म स्क्रीन गेट की व्यवस्था की गई है।

कोलकाता में मेट्रो परियोजना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी। तब से, कमीशन की गई मेट्रो का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कमीशन की गई मेट्रो
1972 से 2014 (42 वर्ष)	28 किलोमीटर
2014 से 2025 (11 वर्ष)	45 किलोमीटर

वर्तमान में, कोलकाता और उसके आसपास कुल 52 किलोमीटर के 4 मेट्रो गलियारे हैं, जिनमें से 20 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार से संबंधित जनोपयोगिताओं के स्थानांतरण संबंधी मुद्दों के कारण लंबित हैं। इन गलियारों की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) जोका - एस्प्लनेड (14 कि.मी.):- जोका - माझेरहाट (7.74 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और माझेरहाट से एस्प्लनेड (6.26 कि.मी.) तक का शेष कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
1.	खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन	• उपयोगिता स्थानांतरण और सड़क यातायात विपथन, 837 वर्गमीटर स्थायी और राज्य सरकार (कोलकाता सशस्त्र पुलिस) की 1,702 वर्गमीटर अस्थायी भूमि की आवश्यकता है। राज्य

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
		सरकार को 24.08.2020 में इस भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। • उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई। • अत्यधिक विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार ने अंततः लगभग 5 वर्ष बाद जुलाई 2025 में ही अनुमोदन प्रदान किया है।
2.	डॉ. बी.सी. रॉय मार्केट	• एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए, रक्षा विभाग की भूमि पर बी.सी. राय मार्केट में स्थिति 528 अनधिकृत दुकानों का अस्थायी रूप से स्थानांतरण अपेक्षित है। • फरवरी, 2022 में इन दुकानों के अस्थायी/स्थायी स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इन अनधिकृत दुकानों के अस्थायी स्थानांतरण के लिए दुकानें भी रेलवे द्वारा बनाई गई हैं। • राज्य सरकार से इन्हें स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है। • यह मामला 3.5 वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

(ii) न्यू गरिया-दम दम एयरपोर्ट (32 कि.मी.): न्यू गरिया - बेलेघाटा (9.8 किमी) को कमीशन कर दिया गया है और बेलघाटा से दम दम एयरपोर्ट (22.2 कि.मी.) तक का शेष कार्य शुरू हो गया है। बहरहाल, निम्नलिखित समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है:

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
1.	चिंगरीघाटा क्रॉसिंग (बेलघाटा - गौर किशोर घोष स्टेशनों के बीच)	• चिंगरीघाट क्रॉसिंग पर वायडक्ट सेगमेंट लॉन्चिंग के लिए सड़क के दोनों किनारों पर (प्रत्येक रात 8 घंटे) प्रत्येक तीन रातों के लिए अस्थायी यातायात डायवर्जन अपेक्षित है। • यह प्रस्ताव दिसंबर, 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत किया गया था। • कोलकाता यातायात पुलिस की इच्छानुसार पहले ही डायवर्जन रोड का निर्माण फरवरी 2025 में किया जा चुका है। • इसके पश्चात्, अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस विभिन्न अधिकारियों के साथ कई बैठकें की जा चुकी हैं। • लगभग 10 महीनों के बाद भी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) नोआपाड़ा-बारासात (18 कि.मी.): नोआपाड़ा - जय हिन्द एयरपोर्ट (6.77 कि.मी.) कमीशन कर दिया गया है और जय हिन्द एयरपोर्ट से माइकल नगर तक का कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, न्यू बैरकपुर से बारासात (7.5 कि.मी.) तक कार्य को भूमि अधिग्रहण और राज्य प्राधिकारियों के साथ अतिक्रमण से संबंधित मुद्दों के कारण रोक दिया गया है।

क्र.सं.	स्थान	मुद्दे
1.	न्यू बैरकपुर से बारासात	• इस खंड में भूमि अधिग्रहण (23,000 वर्ग मीटर) और भारी अतिक्रमणों (1,277 झोपड़ियाँ, 764 दुकानें) को हटाना शामिल है।

		• पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह मामला अभी तक हल नहीं किया गया है।

(iv) वराहनगर - बैरकपुर - दक्षिणेश्वर (14.5 कि.मी.): वराहनगर - दक्षिणेश्वर (2 कि.मी.) को कमीशन किया जा चुका है और वराहनगर से बैरकपुर (12.5 कि.मी.) तक शेष कार्य राज्य सरकार की प्राधिकरणों द्वारा संरेखण में लंबित उपयोगिता स्थानांतरण की वजह से रूका हुआ है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
1.	वराहनगर से बैरकपुर	• मेट्रो रेलवे, आरवीएनएल और कोलकाता नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार 2011 में बी.टी. रोड के साथ मूल संरेखण पर सहमति व्यक्त की गई थी। • समझौता ज्ञापन के अनुसार, मौजूदा पाइपलाइन को राज्य सरकार द्वारा नई 64 इंच व्यास पाइपलाइन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। • इस पाइपलाइन का स्थानांतरण 2012 में पूरा किया गया था। • बहरहाल, पश्चिम बंगाल सरकार से अभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पश्चिम बंगाल में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 2555.22 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

******